योजना आयोग की समस्या एवं नीति आयोग के गठन का विश्लेषणात्मक अध्ययन।

पुष्पांजलि कुमारी

केन्द्र में सरकार बनाने के बाद योजना आयेाग की जगह नीति आयोग बना चुके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आयोग के कामकाज से खुश नहीं है। नीति आयेाग द्वारा कृषि क्षेत्र पर प्रधानमंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट पर भी मोदी ने नाराजगी जताई है।[7] इसका अर्थ तो हम यही समझ सकते है कि स्वयं के निर्णय से ही मोदी खुश नहीं है। अतः होना तो यह चाहिए था कि योजना आयेाग पहले से और मजबूत किया जाता। और इसे पूँजीपति वर्ग के नियंत्रण से दूर रखा जाता एवं पंचवर्षीय योजनाओं के कार्य को भी और सुधारा जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआऔर योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। इस निर्णय में और इस निर्णय की प्रक्रिया में न तो पारदर्शिता थी और न ही भागीदारी। इतने बडे निर्णय का औचित्य तय करने वाली कोई प्रामाणिक रिपोर्ट देश के लोगों के सामने नहीं आई। अतः अब यह जरूरी है कि योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के महत्व पर परिवक्त चर्चा हो ताकि इनके महत्व को अधिक व्यापक स्तर पर समझा जाए। यदि देश में योजनाबद्ध विकास और पंचपर्षीय योजनाओं का दौर नए सिरे से आरंभ हो सके तो हमारे अल्पकालीन विकास और उससे भी अधिक दीर्घकालीन विकास को बहुत सहायता मिलेगी एवं समाजवाद की स्थापना होगी।